

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष – 02

अंक – 05

बेमेतरा, शुक्रवार 22 अगस्त 2025

रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित

कुल पेज – 08

मूल्य – 5 रुपये

संक्षिप्त समाचार

अहमदाबाद के स्कूल में 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र की चाकू मारकर जान ली

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में एक चौकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 8वीं के छात्र पर 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। घटना खोखरा स्थित सेवेंथ डे एडवेंटेस्ट स्कूल में मंगलवार को उस समय घटी, जब स्कूल की छुट्टी हुई थी। छात्र ने 15 वर्षीय छात्र पर स्कूल गेट के बाहर हमला किया था। बुधवार को छात्र की इलाज के दौरान मौत होने पर स्थानीय लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों छात्रों के बीच कक्षा में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद कक्षा आठ के छात्र ने स्कूल के बाहर 7-8 छात्रों का समूह बुलाकर 10वीं के छात्र को घेर लिया। तभी उनमें से एक ने छात्र के पेट में चाकू चोंप दिया। छात्र घायल अवस्था में स्कूल के अंदर गया, जहां सुरक्षाकर्मी ने प्रधानाचार्य को बताया और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। छात्र ने बुधवार को दम तोड़ दिया।

दिल्ली में दृश्यम स्टाइल में पत्नी की हत्या, शव ऐसी जगह छिपाया कि भनक न लगे

नईदिल्ली। दिल्ली में एक महिला की हत्या और उसके शव को ठिकाने लगाने का ऐसा मामला सामने आया कि लोकप्रिय फिल्म दृश्यम की याद ताजा हो गई। यहां एक व्यक्ति ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी की हत्या कर उसके शव को कब्रिस्तान में दफना दिया, जिससे लोगों को भनक नहीं लगी कि उसकी हत्या हुई है। आरोपी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का अमरौहा निवासी पेंटर शबाब अली (47) और मृतक पत्नी फातिमा हैं। आरोपी ने शक के कारण पत्नी की हत्या की। महरीली थाने में फातिमा (30) की दोस्त ने 10 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और शक जताया था कि उसके बंधक बनाया गया है। पुलिस ने जांच शुरू की तो इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज में फातिमा 31 जुलाई को अपने पति शबाब और उसके दोस्तों के साथ दिखी। वह कार में थी और उसे होश नहीं था। इसके बाद पुलिस ने उसके पति से पूछताछ करना शुरू किया। पहले उसने गुमराह किया, लेकिन बाद में सच्चाई बताई।

जयपुर में घर से खेलने निकले 2 भाईयों के शव कार के अंदर मिले, हत्या की आशंका

जयपुर। राजस्थान के जयपुर में एक बंद कार के अंदर 2 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों सगे भाई थे और घर से खेलने निकले थे। घटना गलता गेट थानाक्षेत्र के नागतलाई इलाके में देर रात घटी है। मृतक बच्चों की पहचान 5 वर्षीय अनस और 7 वर्षीय अहसान के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि जिस एसयूवी कार में बच्चों के शव मिले हैं, वह उनके घर से करीब 20 मीटर दूर खड़ी थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शाम को दोनों बच्चे घर से बाहर खेलने निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। रात अधिक होने पर खोजबीन शुरू की गई।

अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई कार्यवाही

विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर बिरला ने लगाई लताड़

नई दिल्ली/ एजेंसी

लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। जिस पर लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को लताड़ लगाई और कहा कि सदन में विपक्ष का आचरण लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप नहीं रहा। ये संसद की गरिमा के अनुसार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता देख रही है कि किस तरह से अहम मुद्दों पर चर्चा को बाधित किया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। जिसमें लोकसभा में 12 विधेयक पारित हुए और 55 सवालों के ही मौखिक जवाब दिए गए। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान पीएम मोदी भी सदन में मौजूद रहे। विपक्ष द्वारा गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक को फंड़े जाने पर भाजपा सांसद शशांक मणि ने कहा, ‘यह बहुत गलत आचरण है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आचरण विश्व की सबसे बड़ी पंचायत में शोभा नहीं देता। आज की तारीख में पूरी विश्व की नजर हमारी पंचायत पर है। जनता देख रही है और इनको अगले चुनाव में सबक सिखाएगी।’ बिलों को लेकर लोकसभा में हुए हंगामे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, ‘ये अत्यंत निंदनीय है लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है और उसका भूमिका का सकारात्मक होना जरूरी है। लेकिन इस तरीके से हंगामा करना और ऐसा आचरण का प्रदर्शन करना जो स्वीकार नहीं है आप लोकतंत्र में गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री हैं वो, अगर आपको उनकी किसी बातों से दिक्कत है तो आप सदन के पटल का इस्तेमाल कीजिए, देश को भी सुनने दीजिए आपके बातों को। लेकिन आप सदन चलने नहीं दे रहे हैं हंगामे कर रहे हैं और किस तरीके से बिल को फंडकर



ओम बिरला ने क्या कहा- देश की जनता सब देख रही है

उन्होंने आगे कहा, ‘सदन के अंदर और संसद परिसर में की जा रही नारेबाजी और सुनियोजित व्यवधान हमारी परंपरा नहीं है। विशेषकर इस सत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हमें स्वस्थ परंपराओं का पालन करना चाहिए। सदन के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा के प्रयास होने चाहिए। मैं लगातार सुनियोजित विरोध और नारेबाजी देख रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। संसद के अंदर और बाहर हमारी भाषा अनुशासित और गरिमामय होनी चाहिए।’ सदन में गरिमा बनाए रखने का आह्वान दोहराते हुए बिरला ने कहा, ‘सहमति और असहमति लोकतंत्र की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हमारा सामूहिक प्रयास यह होना चाहिए कि हम संसद की गरिमा, शांति और गरिमा बनाए रखें।

आप मुंह पर फेंक रहे हैं ये तो कांग्रेस और विपक्ष की परंपरा रही है। ये इनकी कार्यशैली को दर्शाता है इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने बताया कि इस सत्र में 419 सवाल किए गए, जिसमें से सिर्फ 55 के मौखिक उत्तर दिए जा सके। पूरे सत्र के दौरान चर्चा का समय 120 घंटे निर्धारित किया गया था, लेकिन 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। लोकसभा में 12 विधेयक पारित हुए। इससे

120 घंटे की योजना, केवल 37 घंटे हुए काम-बिरला

मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी। इस पहले सभी दलों ने तय किया था कि कुल 120 घंटे चर्चा और कामकाज के लिए दिए जाएंगे। वहीं व्यापार सलाहकार समिति ने भी इस पर सहमति जताई थी। लेकिन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि लगातार गतिरोध और योजनाबद्ध हंगामों के कारण, सिर्फ 37 घंटे 7 मिनट ही प्रभावी कामकाज हो पाया। इसके बावजूद, सरकार ने इस छोटे समय में 14 विधेयक पेश किए और 12 महत्वपूर्ण कानून पास कराए। इनमें ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा और नियमन विधेयक, 2025 और खनिज और खनन (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 के साथ-साथ राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 प्रमुख हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजजू ने कहा कि यह सत्र सरकार और देश के लिए सकारात्मक और फलदायी रहा।

पहले गुरुवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही तुरंत ही स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर शुरू हुई, जिसमें ओम बिरला ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि पूरे सत्र के दौरान बार-बार कार्यवाही बाधित करने के प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए आत्मचिंतन का समय है, क्योंकि विपक्ष ने भर चले सत्र के दौरान ज्यादा चर्चा नहीं हो सकी।

दिल्ली के 50 से अधिक स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, दहशत फैली

नईदिल्ली। दिल्ली के 32 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के 48 घंटे बाद फिर से 50 से अधिक स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मालवीय नगर स्थित एसकेवी हौज रानी और करोल बाग स्थित आंध्रा स्कूल समेत 50 स्कूलों को बुधवार सुबह अज्ञात ईमेल मिले हैं। सूचना के बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग स्कॉयड की टीम मौके पर पहुंच गई। परिसर खाली करा लिया गया है। धमकी की सूचना के बाद पुलिस ने स्कूल परिसर को खाली करा दिया, जबकि कुछ बच्चों को वापस घर भेज दिया गया।

एक्ट्रेस से गंदी बात पर फंसे राहुल ममकूटथिल

देना पड़ा केरल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा...

नई दिल्ली। एजेंसी

कांग्रेस विधान सभा सदस्य (एमएलए) राहुल ममकूटथिल पर लेखिका हनी भास्करन और मॉडल रिनी एन जॉर्ज द्वारा लगाए गए अश्लील आचरण के आरोप हैं। नतीजतन, उन्होंने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आज, केरल के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता वी.डी. सतीसन ने कांग्रेस विधायक और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राहुल ममकूटथिल पर लेखिका हनी भास्करन और अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज द्वारा अनुचित संदेश भेजने और अश्लील आचरण में लिप्त होने के

पार्टी में गुटबाजी की तो खैर नहीं अभिषेक बनर्जी

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने आज संगठन मजबूत करने के लिए बारासात संगठनात्मक ज़िले के नेताओं के साथ अहम बैठक की। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस बैठक में उन्होंने गुटबाजी को लेकर कड़ा संदेश दिया और स्पष्ट कहा कि पार्टी में किसी भी तरह की आपसी लड़ाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक को लेकर पार्टी सूत्रों ने बताया कि बारासात ज़िले में कई बार गुटीय संघर्ष की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके मद्देनजर अभिषेक बनर्जी ने यह चेतावनी दी।



आरोपों पर बात की। सतीशन ने कांग्रेस पार्टी द्वारा गहन जाँच का आश्वासन दिया और जोर देकर कहा कि अगर आरोप गंभीर पाए गए तो कोई हिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा पार्टी आरोपों की जाँच करेगी। हम आरोपों की गंभीरता की जाँच करेंगे। अगर यह बहुत गंभीर है, तो हम आवश्यक

कार्रवाई करेंगे। एक प्रक्रिया है; उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। हम तुरंत निर्णय लेंगे, कोई देरी नहीं होगी। पार्टी के समक्ष कोई शिकायत नहीं है। अगर कोई कोई आरोप लगा रहा है, तो हम उसकी जाँच करेंगे। हम इसे बहुत गंभीरता से लेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे, कोई दया नहीं होगी। इस बीच, महिला कांग्रेस नेता बिंदु कृष्णा ने कहा, महिला कांग्रेस ने पार्टी को अपना रुख बता दिया है। पार्टी को जवाब देना है और पार्टी उचित निर्णय लेगी। मुझे राहुल ममकूटथिल के खिलाफ पहले कोई शिकायत नहीं मिली है।

असम सरकार का बड़ा फैसला

18 साल से ऊपर वालों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता मिलने से रोकने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को असम में पहली बार आधार कार्ड नहीं मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में 18 वर्ष से अधिक आयु के चाय जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को केवल एक वर्ष तक ही आधार कार्ड मिलता रहेगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, यदि अभी तक आधार



कार्ड नहीं मिला है, तो आवेदन करने के लिए केवल एक महीने का समय दिया जाएगा। हालाँकि, उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के चाय जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगले एक वर्ष तक आधार कार्ड मिलते रहेंगे।

आरोपी राजेश को पांच दिन की पुलिस रिमांड

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा....

नई दिल्ली/ एजेंसी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जेड श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान कर दी है। इससे पहले, दिल्ली में बुधवार को साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी राजेश खिमजी को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी राजेश को दिल्ली पुलिस ने देर रात दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका स्थित एक



मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया गया। सूत्रों ने बताया कि आरोपी को तीस हजारी अदालत परिसर में किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी आवास पर बुधवार सुबह साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान परियादी

बनकर आए एक युवक ने अचानक मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। आरोपी ने सीएम को कुछ पेपर दिए इसके बाद उसने चिल्ला न शुरू कर दिया। बाद में आरोपी ने सीएम का हाथ और बाल पकड़े और उनके साथ धक्का-मुक्की करने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि आरोपी ने सीएम को थपड़ भी मार दिया। हालाँकि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने थपड़ मारने की बात से इंकार किया है। आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। वहां मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी ने किया नामांकन, खरगे-सोनिया रहे मौजूद.....

उपराष्ट्रपति चुनाव भारत के विचार की पुष्टि का विषय-सुदर्शन रेड्डी

नई दिल्ली/ एजेंसी

विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी ने राज्यसभा महासचिव (जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी भी हैं) के समक्ष नामांकन पत्रों के चार सेट जमा किए। राकांपा (सपा) प्रमुख शरद पवार, सपा नेता रामगोपाल यादव, द्रमुक के तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी रॉय, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, माकपा के जॉन ब्रिटान नामांकन के लिए उपस्थित विपक्षी नेताओं में शामिल थे। लगभग 160 सांसदों ने प्रस्तावक और

समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन दस्तावेजों की जांच की और रेड्डी को एक पावती पच्ची सौंपी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी अपना वोट डालने के पात्र होते हैं। निर्वाचक मंडल की प्रभावी संख्या 781 है और बहुमत का आंकड़ा 391 है। सत्तारूढ़ एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है। सत्तारूढ़ दल को कम से कम 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। वार्डएसआरसीपी जैसी विपक्षी गठबंधन से इतर पार्टियां पहले ही राधाकृष्णन को समर्थन देने की घोषणा कर चुकी हैं। इससे पहले बुधवार को खरगे ने घटक दलों के नेताओं से उनका परिचय करवाया। संसद के केंद्रीय कक्ष में खरगे



के साथ पहुंचे सुदर्शन का स्वागत करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे। उनके साथ हुई बैठक में गठबंधन के सभी सहयोगियों ने अपना पक्ष रखा। नामांकन से पहले खरगे ने

कहा था कि बी. सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव केवल एक पद के लिए प्रतियोगिता नहीं है। यह हमारे राष्ट्र की आत्मा के लिए एक वैचारिक लड़ाई है। जहां सत्तारूढ़ दल ने आरएसएस की

विचारधारा को चुना है, वहीं हम संविधान और उसके मूल्यों को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति पर संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। यदि मैं निर्वाचित होता हूं तो मैं निष्पक्षता, गरिमा तथा संवाद एवं शिष्टाचार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ अपनी भूमिका निभाने का वचन देता हूं। इस दौरान विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी ने विपक्षी दलों के नेताओं के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में विश्वास और हमारे लोगों में आशा के साथ मैं इस यात्रा पर निकल रहा हूं। हमारी लोकतांत्रिक भावना हम सभी का मार्गदर्शन करती रहे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं।

अगर निर्वाचित हुए तो निष्पक्षता के साथ निभाऊंगा उपराष्ट्रपति पद की भूमिका

उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति पर संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। यदि मैं निर्वाचित होता हूं तो मैं निष्पक्षता, गरिमा तथा संवाद एवं शिष्टाचार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ अपनी भूमिका निभाने का वचन देता हूं। इस दौरान विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी ने विपक्षी दलों के नेताओं के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में विश्वास और हमारे लोगों में आशा के साथ मैं इस यात्रा पर निकल रहा हूं। हमारी लोकतांत्रिक भावना हम सभी का मार्गदर्शन करती रहे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी अपना वोट डालने के पात्र होते हैं।



'' आदि कर्मयोगी अभियान '' : जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित, 35 चिन्हांकित ग्रामों में बनेगा 01-01 आदि सेवा केन्द्र

जिले के 22 हजार 890 से अधिक जनजातीय नागरिकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य

मुंगेली /मूक पत्रिका



आदिवासी विभाग द्वारा संचालित “आदि कर्मयोगी अभियान” के अंतर्गत बीते गुरुवार को कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं कल्याण से जुड़े हुए प्रमुख योजनाओं की संतुष्टि सुनिश्चित करना है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” तथा सेवा, समर्पण और संकल्प से प्रेरित है। कार्यक्रम में कलेक्टर कुन्दन कुमार ने कहा कि केन्द्र शासन द्वारा जनजातीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से यह नई पहल की शुरुआत की गई है। यह अभियान आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का एक व्यापक प्रयास है। इस अभियान के

अंतर्गत जिले के तीनों विकासखण्डों के 35 आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के 05 हजार 498 परिवार के 22 हजार 890 से अधिक जनजातीय नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में कुल 35 चिन्हांकित ग्रामों में 01-01 आदि सेवा केन्द्र (एकल खिड़की सेवा केन्द्र) का निर्माण किया जाएगा, जिसे ‘वन-स्टॉप सेवा केन्द्र’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इन केन्द्रों पर विभागीय संपर्क विवरण, योजनाओं की जानकारी, शिकायत निवारण रजिस्टर जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इसके साथ ही आदि

सेवा केन्द्र के माध्यम से संबंधित ग्राम के विकास, अधोसंरचना एवं बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए इन सभी के द्वारा संयुक्त रूप से अधिसरण के माध्यम से ग्राम विकास योजना बनाया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत प्रभाकर पांडेय ने कहा कि ‘आदि कर्मयोगी योजना’ का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं की क्रियान्वयन प्रणाली को दुरुस्त करना है। उन्होंने सभी प्रशिक्षकों को अपने प्रशिक्षण के अनुभव को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने कहा। अभियान के अंतर्गत

आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी एवं आदि साथी के माध्यम से जनजातीय गांवों में विभिन्न योजनाओं में क्रिटिकल गैप को चिन्हांकित कर योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों से जुड़े जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने ली प्रेसवार्ता, अभियान के संदर्भ में दी जानकारी

कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में प्रेसवार्ता कर ‘आदि कर्मयोगी अभियान’ के संबंध में मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी। उन्होंने योजना का उद्देश्य, जिले में क्रियान्वयन सहित अभियान के संबंध में विस्तार से बताया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय, अपर कलेक्टर राजेन्द्र गुप्ता, संबंधित अधिकारी और विभिन्न मीडिया के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

जनता की हर समस्या का समाधान सुनिश्चित करना हमारा संकल्प है-अनुज

जनदर्शन में विधायक ने सुनी लोगों की समस्याएं-कई समस्याओं का किया त्वरित निराकरण

धरसीवां/मूक पत्रिका

विधायक अनुज शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंच कर उनकी समस्याएं सुनी तथा उनके निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीते गुरुवार दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक अपने विधायक जनदर्शन कार्यक्रम खरोरा में लोगों के बीच रह कर उनकी समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान भी किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि विधान सभा चुनाव के बाद प्रति गुरुवार को खरोरा जनदर्शन कार्यक्रम आरम्भ किया गया था परंतु क्षेत्रीय दौरा के चलते इसे स्थगित किया गया था। जो अब पुनः शुरु हो गया है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं का निराकरण किया जाता है।जनदर्शन का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाना है। आम आदमी को छोटे-छोटे काम के लिए भटकना न पड़े, कर्मचारी-अधिकारी नियम-कानून का अड़ंगा लगाकर



जनसामान्य को परेशान न करें। इसकी अब सतत निगरानी की जाएगी। आम आदमी को परेशान कर शासन की छवि धूमिल करने वाले अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि क्षेत्र के किसान, गरीब, मजदूर और अतिम

छोर के व्यक्ति को कोई परेशानी न हो, यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीनी स्तर पर हितग्राहियों को लाभान्वित करने संबंधित अधिकारी कमर कस लें, इसमें लापरवाही नहीं चलेगी।

शासकीय एम एम आर स्नातकोत्तर महाविद्यालय चाम्पा में इको क्लब के तत्वाधान में किया गया पौधारोपण



जांजगीर चांपा /मूक पत्रिका

शासकीय एम एम आर स्नातकोत्तर महाविद्यालय चाम्पा में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इको क्लब के तत्वावधान में किया गया पौधारोपण। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ एच पी खैरवार के मार्गदर्शन में महाविद्यालय के

वानस्पतिक उद्यान में एक पेड़ भाँ के नाम से लगाया गया। महाविद्यालय में इंसुलिन, भुई नीम, गुडहल, आँवला, गुलाब, ब्रायोफिलम, अपराजिता, आम, अमरुद आदि पौधे लगाए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ खैरवार, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ बी डी दीवान, प्रो आर आर साहू, डॉ महिपाल, डॉ भारद्वाज, डॉ व्ही एम दांडेकर, डॉ व्ही के शर्मा, डॉ मिरो,

डॉ डी एन बंजारे, डॉ सुनीता रावैर, प्रो मीनाक्षी चंद्रा, इकोक्लब प्रभारी डॉ नीलिमा पाण्डेय, प्रो विवेक जायसवाल, प्रो अनुराधा रावैर, प्रो हंसराज, शिव सूर्यवंशी, जे के दीवान, संतोष तिवारी, हेम बाई यादव , लक्ष्य, कार्तिक सभी पौधे लगाए। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी एवं छात्र/ छात्राएँ उपस्थित थे।

पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में थाना चांपा पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफकी गई सख्त कार्रवाई

धारदार हथियार के साथ 02 आरोपी चढ़े चाँपा पुलिस के हत्थे

जांजगीर चांपा /मूक पत्रिका

आरोपियों द्वारा धारदार हथियार के साथ आने वाले लोगों को हथियार लहराकर कर रहे थे भयाक्रांत। दोनों आरोपियों को धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।गिरफ्तार आरोपियों का नाम- 1- शंकर दास महंत उर्फ विष्णु पिता संतोष दास महंत 26 वर्ष निवासी शंकर नगर चाँपा। 2-रोहन चौहान पिता तीरथराम चौहान 19 वर्ष निवासी तिलक नगर तालाब पारा चाँपा उपरोक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता, सहित स्टॉफ का विशेष योगदान रहा।



शिवसेना ने ग्राम कोहड़िया जनसुनवाई में आपत्ति दर्ज कराई



बेमेतरा/मूक पत्रिका

शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव दाऊ राम चौहान ने कहा कि ग्राम कोहड़िया में बृजेश स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जनसुनवाई में जिला प्रशासन के द्वारा रखा गया था उक्त जनसुनवाई कार्यक्रम में शिवसेना पार्टी के जिला प्रमुख गिरवा रजक, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष रामचरण वर्मा, नवागढ़ विधानसभा प्रमुख

नारायण वर्मा, नवागढ़ विधानसभा सचिव अनिल वर्मा, पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता वीरेंद्र कुमार निषाद के द्वारा आपत्ति दर्ज किया आगे चौहान ने कहा कि उक्त ग्राम में प्रदूषण युक्त फैक्ट्री खुलने से जनजीवन एवं कृषि को प्रभावित होगा उक्त क्षेत्र के 10 से 15 किलोमीटर ग्रामीणों को प्रदूषण एवं क्षति प्रधान जिला बेमेतरा को ध्यान में रखते हुए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने आपत्ति दर्ज किया।

आगामी गणेश चतुर्थी एवं नवरात्रि पर्व को दृष्टिगत रखते हुए थाना चांपा क्षेत्र के समस्त मूर्तिकारों की बैठक की गई आयोजित

■ मूर्तिकारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की स्टाइलिश, फिक्की शैली या विकृत स्वरूप की मूर्तियाँ नहीं बनाई जाए नहीं तो होगी कार्रवाई

जांजगीर चांपा /मूक पत्रिका

आगामी गणेश चतुर्थी एवं नवरात्रि पर्व को दृष्टिगत रखते हुए थाना चांपा क्षेत्र के समस्त मूर्तिकारों की बैठक थाना परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी मूर्तिकारों को यह समझाइश दी गई कि वे केवल देवी-देवताओं की मूल स्वरूप अनुसार मूर्तियों का निर्माण करें। मूर्तिकारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की स्टाइलिश,



फिक्की शैली या विकृत स्वरूप की मूर्तियाँ नहीं बनाई जाएँगी। यदि ऐसा किया जाता है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी यह कार्रवाई स्थानीय धार्मिक अनुयायियों द्वारा पुलिस अधीक्षक, जिला जांजगीर-चांपा को दिए गए ज्ञापन के परिपालन में की गई। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने मूर्तिकारों की तैयार मूर्तियों का निरीक्षण किया तथा यह सुनिश्चित किया कि सभी मूर्तियाँ भगवान के परंपरागत स्वरूप में ही

हों।इस अवसर पर मूर्तिकारों ने भी प्रशासन के निर्देशों का पूर्ण समर्थन करते हुए लिखित में सहमति दी कि वे आगे से केवल देवी-देवताओं की मूल स्वरूप की मूर्तियों का ही निर्माण करेंगे। पुलिस विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि वे पर्व-त्योहारों को सामाजिक सौहार्द एवं परंपरागत मर्यादा के साथ मनाएँ और किसी भी प्रकार की भ्रामक या विकृत मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

थाना सारागांव पुलिस द्वारा अलग- अलग जगहों से अवैध शराब बिक्री करने वाले 02 आरोपियों को किया गिरफ्तार

जांजगीर चांपा /मूक पत्रिका

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन पर जिले में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लाने के लिए पुलिस द्वारा की जा रही है लगातार कार्यवाही।दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।पुलिस अधीक्षक जांजगीर - चाम्पा के निर्देशन में जिला पुलिस जांजगीर द्वारा अवैध शराब पर अंकुश लाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना सारागांव पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया जिसमें आरोपी नाथु राम बरेठ उम्र 50 साल निवासी देवरी थाना सारागांव के कच्चे से 36 पाव देशी प्लेन शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त



एक मोटर सायकल तथा आरोपी अभिषेक रत्नाकर उम्र 20 साल निवासी डबरीपारा सारागांव के कच्चे से 07 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जुमला किमती 3100/ रूपया बरामद किया जाकर आरोपियों के विरुद्ध अलग-अलग अपराध धारा

34 (2) भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सुभाष चौबे थाना प्रभारी सारागांव का सराहनीय योगदान रहा।

पेशी की डेट बार-बार ना बढ़ाएं, राजस्व प्रकरणों का समय पर निराकरण अनिवार्य - कलेक्टर

कलेक्टर ने किया तहसील कार्यालय पामगढ़, शिवरीनारायण का औचक

समय सीमा के बाहर के प्रकरणों का कैम्प कोर्ट लगाकर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश

त्रुटि सुधार संबंधी सभी प्रकरणों का निराकरण त्रुटि सुधार मॉड्युल के माध्यम से मौके पर ही करें

उप पंजीयक कार्यालय, स्कूल व डिजिटल रॉप सर्वे का निरीक्षण

जांजगीर चांपा /मूक पत्रिका

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बीते गुरुवार को पामगढ़ एवं शिवरीनारायण तहसील कार्यालय, उप पंजीयक कार्यालय, स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील एवं एसडीएम कार्यालय में नामांतरण, अविवादित व विवादित बंटवारे, अभिलेख दुरुस्ती, त्रुटि सुधार,



सीमांकन से संबंधित प्रकरणों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी

प्रकरण की पेशी की तिथि अनावश्यक रूप से बार-बार न बढ़ाई जाए। कलेक्टर ने समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जतायी। उन्होंने कहा कि समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण प्राथमिकता में किया जाए और इसके लिए कैम्प कोर्ट लगाकर मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें। साथ ही त्रुटि सुधार संबंधी सभी प्रकरणों का निराकरण त्रुटि सुधार मॉड्युल के माध्यम से मौके पर ही किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व प्रकरणों को ई-कोर्ट में दर्ज किया जाए, जिससे उनकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग आसान हो सके। साथ ही रिकार्ड दुरुस्तीकरण और त्रुटि सुधार के मामलों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। कलेक्टर ने कहा कि यदि त्रुटि सुधार के प्रकरण में फ़ैल्ड के कर्मचारियों द्वारा जानबूझ के त्रुटि की गई है तो संबंधितों को नोटिस जारी कर अनुशासत्वक कार्रवाई करे। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में आने वाले आवेदकों से बातचीत की और उनकी शिकायतों को सुना। इस अवसर पर एसडीएम

जांजगीर सुब्रत प्रधान, एसडीएम पामगढ़ देवेन्द्र चौधरी सहित तहसीलदार, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने ग्राम मेंहेदी में खेतों में पहुंचकर डिजिटल फसल सर्वेक्षण के कार्य का किया निरीक्षण -

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने ग्राम मेंहेदी में खेतों में पहुंचकर डिजिटल फसल सर्वेक्षण के कार्य का किया निरीक्षण किया। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को डिजिटल फसल सर्वेक्षण के कार्यों का सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं कुशलतापूर्वक करने को कहा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को डिजिटल फसल सर्वेक्षण हेतु निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल सर्वे से किसानों को बेहतर सुविधा और योजनाओं का लाभ मिलेगा, डिजिटल सर्वे का कार्य को त्रुटिरहित समय पर पूर्ण करने कहा।

संपादकीय

कई शहरों में एक-दो घंटे की बरसात में ही सब कुछ ठहर-सा जाता है और चारों ओर बाढ़ का दृश्य बन जाता है। यह निश्चित रूप से अनियोजित शहरी विकास का नतीजा है, जहां बाढ़ अच्छी सड़कों को तबाही दी जाती है, लेकिन पानी के निकास का उचित और पर्याप्त इंतजाम नहीं किया जाता है। मौसम की अपनी गति होती है और सामान्य स्थितियों में वह परिस्थितिकी चक्र को बनाए रखने का एक जरूरी हिस्सा होती है। मगर पिछले कुछ समय से इसके स्वरूप में तेजी से बदलाव दर्ज किया जा रहा है और

खासतौर पर बारिश की वजह से होने वाली तबाही की तस्वीरें ज्यादा विगड़ती जा रही हैं। यों हर वर्ष मानसून के पूरे मौसम में बारिश की वजह से लेक के ज्यादातर हिस्से कम या ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बरसात अब बेलागम हो रही है और तबाही का सिलसिला-सा बनता जा रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में, फिर जम्मू-कश्मीर के कश्तवाड़ में बरपात फटने और उससे जुड़े जन्मू-कश्मीर की भारी तबाही की जैसी घटनाएं हुईं, उन्होंने देश के नमी की हिस्सों के लोगों को

भी दहला दिया। अब कश्मीर के कठुआ में भी बादल फटने और भूखण्डन की घटना में सारा लोगों की जान चली गई। दूसरी ओर, मुंबई में लगातार तीन दिन की बारिश के बाद हलाल यह हो गई, मानो शहर में बाढ़ आ गई हो। वहाँ कई इलाकों में जलभराव की वजह से जनजीवन पूरी तरह बाधित हो गया, कई जिलों में चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं मराठवाड़ा क्षेत्र में बादल फटने की घटना में नौदेड़ के पांच लोगों के लापता होने की खबर आई है। सिंधु, हिमाचल प्रदेश के कई सहित कई इलाकों में जिस तरह

लगातार बार-बार बादल फटने की घटनाएँ सामने आ रही हैं, उससे समूची स्थानीय आबादी के सामने किसी तरह खुद को बचाने की चुनौती खड़ी हो रही है। यह समझना मुश्किल हो रहा है कि कम या ज्यादा बरसात वाला जिस मानसून को देश की खेती-किसानी के लिए एक जरूरत के तौर पर देखा जाता था, अब वह कई राज्यों में व्यापक तबाही का कारण क्यों बन रहा है। कई इलाकों में अब बारिश के साधारण बादल फटने की घटना में भी हतनी तेज-से बढ़ोतरी क्यों देखी जा रही है? दूसरी ओर, कई शहरों में

एक-दो घंटे की बरसात में ही सब कुछ ठहर-सा जाता है और चारों ओर बाढ़ का दृश्य बन जाता है। यह निश्चित रूप से अनियोजित शहरी विकास का नतीजा है, जहां बहुत अच्छी सड़कें तो बना दी जाती हैं, लेकिन पानी के निकास का उचित और पर्याप्त इंतजाम नहीं किया जाता है। नतीजतन, दिल्ली जैसे महानगर का बड़ा हिस्सा कुछ देर की घनघोर बरसात में ही जलभराव, सड़क जाम से त्रस्त हो जाता है और पेड़ों के गिरने से होने वाले जानमाल के नुकसान की अनेक घटनाएं सामने आती हैं।

सत्ता पक्ष जहां शासन संचालन और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है, वहीं विपक्ष लोकतंत्र का प्रहरी बनकर उसके हर कदम पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है, असंतोष को स्वर देता है और जनभावनाओं को दिशा देता है। लेकिन वर्तमान विपक्ष इन भूमिकाओं में नकारा साबित हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष अपनी ही बिसात पर मात खा रहा है, जिस तरह से विपक्ष और विशेषतः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी, ईवीएम में गड़बड़ी एवं मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण पर बेतूके एवं आधारहीन आरोप लगाये हैं, उससे संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की गरिमा एवं प्रतिष्ठा तो आहत हुई ही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी कठघरे में दिख रही है।

अपनी ही बिसात पर मात खा रहा है विपक्ष

(ललित गर्ग)

लोकतंत्र का सार यही है कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक-दूसरे के पूरक हों, शत्रु नहीं। विपक्ष को केवल विरोध की राजनीति से बाहर आकर वैकल्पिक दृष्टिकोण देना होगा, और सत्ता-पक्ष को भी यह समझना होगा कि विपक्ष की आलोचना लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है।

भारत की लोकतंत्र विपक्ष का समर्थन बढ़ा लेता है। यह केवल संस्थाओं और मतों का खेल नहीं है, बल्कि ऐसा ऐसी जीवित प्रक्रिया है जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सत्ता पक्ष जहाँ शासन संचालन और नीतियों को लागू करने के लिए विवेकपूर्ण होता है, वहीं विपक्ष लोकतंत्र का प्रतीक बनकर उसके हर कदम पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है, अंतर्दोष को खट्खट देता है और जनभावनाओं को दिशा देता है। लेकिन वर्तमान विपक्ष इन भूमिकाओं में नकारा साबित हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष अपनी ही बिसात पर मात खा रहा है, जिस तरह से विपक्ष और विशेषतः काँग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी, ईवीएम में गड़बड़ी की मसलता सूचियों के विशेष गहन पक्षीयण पर बेतुके एवं आधारहीन आरोप लगाये हैं, उससे संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की गरिमा एवं प्रभुता तो आहत हुई ही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी कठघरे में दिख रही है। यह अच्छा हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर वोट चोरी वाले ऐह गद्गद् ही बेहूदा, आधारहीन एवं गुमराह करने साहित राहुल गांधी के आरोपों का न केवल बिन्दुवार जबाब दिया, बल्कि उन्हें बेनकाब करते हुए यह भी कहा कि वे या तो अपने निराधार आरोपों के सम्बंध में शपथ पत्र दे या सत्ता दिनों के भीतर देश से सदाफ्री मांगें। निश्चित ही राहुल गांधी को ऐसी चेतावनी देना आवश्यक हो गया था, क्योंकि वे अपने संकीर्ण एवं स्वार्थी राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिये लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को धुंधलाने की सारी हदें पार चुके हैं।

हलक के दिनों में जिस तरह चुनाव आयोग, मतदाता सूची और वोट प्रणाली के आरोपों को लेकर बहस छिड़ी है, उससे इस प्रश्न को फिर से गहराई से सोचने को बाध्य किया है कि क्या लोकतंत्र विश्व बेबुनियाद आरोप लगाते हुए अपनी भूमिका को प्रश्नों के घेर में कब तक डालता रहेगा? विश्व बिना ठोस प्रमाण के बड़े आरोप लगाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े कर देता है। क्या जुड़े के नाम पर जनता के व्यापक हित से जुड़े सुधारों का विरोध करना विश्व का शाल बन गया है? पिछले एक दशक से विश्व लोकतंत्र को उसके बनाने की अपनी भूमिका की बजाय कमजोर एवं जर्जर करने में जुटा है। उसने सत्ता-पक्ष को घेरने के लिये जरूरी मुद्दों को सकारामक तरीकों से उठाने की बजाय विध्वंसामक तरीकों से विकास के जनहितकारी मुद्दों को भी विवाद का मुद्दा बनाते हुए सारी हद्दें पार

कर पार दी हो। आधार को बैंक अकाउंट से जोड़ने का मामला हो। यान्त्रिक 370 को खत्म करना हो। सीएफ-एनआरसी का मामला हो या हाल में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण अभियान हो। विपक्ष मोदी सरकार के इन विकासमूलक सुधारों को जर्नलिट के खिलाफ बताते हुए मूख्य विरोध कर रहा है। जो लोकतंत्र को धुंधलाने का एक बड़ी साजिश प्रतीत होता है। निश्चित ही विपक्ष को इन खूबियाँ तम में सबसे बड़ी क्षति जन्ता का आस्था की होती है। जब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं

लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ है कि जनता और राजनीतिक दल चुनाव आयोग व अन्य संस्थानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं कर पा रहे। इसलिए न्यायपालिका की भूमिका भी अब केवल विवाद सुलझाने की नहीं रह गई है, बल्कि लोकतंत्र के विकास को पुनः स्थापित करने की हो गई है, जबकि यह कार्य राजनीतिक दलों एवं चुनी हुई सरकारों का होता है।

लोकतंत्र का सार यही है कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक-दूसरे के पूरक हों, शत्रु नहीं। विपक्ष को केवल विरोध की राजनीति से बाहर आकर

जाता है। आज भारत का विपक्ष जिस तरह संसद को टपक करे, व्यक्तिगत हमलों, दुष्प्रचार और असंवैधानशील आचरण पर आमादा है, उसने लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुँचाई है। संसद सत्र, जहाँ जनता की समस्याओं का समाधान खोजा जाने चाहिए, वहाँ विपक्ष का रवैया अवरोध पैदा करने वाला अधिक दिखाता है। महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर सार्थक चर्चा के बजाय नारेबाजी और वॉक-आउट आम बात हो गई है। यह स्थिति केवल संसद की ही नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए घातक है। इतिहास गवाह है कि जब-जब विपक्ष ने



की निष्पक्षता संदिग्ध बनाई जाती है, तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। लोकतंत्र में हार-जीत से भी बड़ा मुद्दा चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता होता है।

विषय केवल सत्ता की आलोचना करने के लिए नहीं है। उसका दायित्व है कि वह जनता की समस्याओं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी की असह्योक्तपूर्ण वसूली, पर्यावरण, सफाई, नारी की असुरक्षा जैसे चलते मुद्दों को उजागर करे, ठोस विकल्प प्रस्तुत करे और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती में योगदान दे। केवल आरोप-प्रत्यारोप में उलझकर विद्वत् विषय अपनी ऊर्जा खर्च कर देता है तो वह जनता का विश्वास खो देता है। यही कारण है कि आज विषय की स्थिति कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि वह केवल आरोप लगाता हुआ दिखता है, समाधान प्रस्तुत करने में पिछड़ जाता है। सत्ता पक्ष को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र केवल बहुमत से नहीं चलता, बल्कि समर्पित और पारदर्शिता से भी चलता है। यदि विषय लगातार विषय उठा रहा है तो सत्ता पक्ष का कर्तव्य है वह धैर्यपूर्वक उत्तर दे, जाँच के रास्ते खोले और हर आरोप को तथ्यों से परखे। विषय को नकार देना लोकतंत्र को कमजोर करना है। जब सत्ता और विषय के बीच टकराव बढ़ता है, तब न्यायपालिका अंतिम सहारा बनती है। यही कारण है कि आज बार-बार सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की माँग उठती है। यह स्थिति लोकतंत्र के

वैकल्पिक दृष्टिकोण देना होगा, और सत्ता-पक्ष को भी यह समझना होगा कि विषय की आलोचना लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। प्रथममंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रारंभ से ही विषय को महत्व दिया है, उन्होंने संवेदनशील सकार के साथ सुनाजमान नेतृत्व का परिचय दिया है लेकिन विषय जब आग्रह, पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह से विरा हो तो सकारात्मक दिशाएँ कैसे उद्घाटित हो सकती हैं? आज की राजनीति में लोकतंत्र और विषय के बीच खींचतान तेज है। यह टकराव लोकतंत्र को कमजोर करने वाला नहीं बल्कि उसे और परिपक्व बनाने वाला होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि विषय अपनी रचनात्मक भूमिका निभाए और सत्ता पक्ष उसकी आलोचना को स्वीकार कर उत्तरदायित्वपूर्ण जवाब दे। तभी लोकतंत्र की असली शक्ति और जनता के विश्वास को बनाए रखा जा सकता है।

लोकतंत्रों को शक्ति केवल सरकार में नहीं बल्कि एक सशक्त और रचनात्मक विपक्ष में भी निहित होती है। विपक्ष लोकतांत्रिक ढाँचे का आवश्यक स्तंभ है, जो सत्ता पर निगरानी रखता है, नीतियों में कमियों को उजागर करता है और जनता की आवाज को सदैव तक पहुँचाता है। लेकिन जब विपक्ष अपनी इस जिम्मेदारी को भूलकर केवल नकारात्मक राजनीति पर उतर आए, तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होने लगती है और देश की छवि तथा स्थिरता पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो

रचनात्मक भूमिका निभाई है तो लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। 1977 में आपातकाल के विरोध से लेकर 1989 तक विपक्ष ने लोकतंत्र को बचाने और पुनर्जीवित करने का कार्य किया। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह विपक्ष अपरिष्कृत, निरंतर बिखरा हुआ, नेतृत्वविहीन और नकारात्मक एजेंडे पर केंद्रित रहा है, उसने लोकतांत्रिक संस्कृति को आघात पहुँचाया है।

विदेशी ताकतें हमेशा से भारत की आंतरिक कमजोरी का फायदा उठाने की फिराक में रहती हैं। जब विपक्ष सरकार की नीतियों का विधि पक्ष करने के नाम पर राष्ट्र-विरोध, राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना की कारगवाई या विदेश नीति तक पर सवाल उठाने लगता है, तो इसका सीधा लाभ पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को मिलता है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल करना विपक्ष का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हालत यही इशारा कर रहे हैं। लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद को 'घिघटन' में बदल देना खतरनाक है। विपक्ष को याद रखना होगा कि उसकी जिम्मेदारी केवल सत्ता पाने की नहीं, बल्कि देश की स्थिरता और विकास को सही दिशा देने की भी है। अगर विपक्ष अपने दायित्वों को नकारात्मक राजनीति में खोता रहता तो यह न केवल उसके लिए बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। आज समय की मांग है कि विपक्ष आत्ममंथन करे।

घुमन्तु समाज को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जरूरी केंद्र व राज्य सरकारों की इच्छाशक्ति

डॉ अतुल मलिकराम (राजनीतिक रणनीतिकार)
भारत की सांस्कृतिक विविधता में घुमंतू समाज एक अनमोल रत्न की तरह है, जो अपनी अनूठी जीवनशैली और परंपराओं के साथ देश की सामाजिक-आर्थिक संरचना का अभिन्न हिस्सा रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह समाज, दशकों से अपनी खानाबदोश प्रकृति के कारण मुख्यधारा से कटा हुआ है और आज भी मूलभूत सुविधाओं व अधिकारों से वंचित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों तक उनकी पहुंच बेहद सीमित है। ऐसे में सवाल उठता है कि आज हम आजादी के 80वें साल में तो प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन घुमन्तु समाज के कल्याण व उत्थान के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाए हैं? क्या घुमंतू समाज के उत्थान को ध्यान में रखकर उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता? क्या राष्ट्रीय स्तर के कॉमन आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनाया जा सकता? क्या उनके लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर धर्मशाला जैसी अस्थायी आवास सुविधा का निर्माण नहीं किया जा सकता? ये केवल सवाल ही नहीं जवाब और सुझाव भी हैं, जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें अमल करके, देश की लगभग 10 फीसदी आबादी को मुख्यधारा में जोड़ सकती हैं।

कई राज्यों में घुमन्तु समुदाय को लेकर बोर्ड का गठन किया गया है, सबसे अधिक जनसंख्या के लिहाज से मध्य प्रदेश राज्य को जैसे राज्य में तो अलग मंत्रालय भी है लेकिन घुमन्तुओं का जीवन स्तर जस का तस है। जन्म से ही अपारार्थिक प्रवृत्ति का धोषित कर दिए गए इस समाज के उत्थान को लेकर अब तक की सभी सरकारों ने जो कदम उठाए हैं उसकी बानगी घुमन्तुओं की वर्तमान परिस्थिति में साफ झलकता है।

घुमन्तु समाज को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए
जरूरी केंद्र व राज्य सरकारों की इच्छाशक्ति

डॉ. अतुल मलिकराम

राजनीतिक रणनीतिकार

📞📞📞@amg24x7

ये समुदाय, जिनमें बंजारा, गडिया लोहार जैसे अन्य कई शामिल हैं, अपनी आजीविका के लिए कई तरह के पारम्परिक व्यवसायों पर निर्भर रहता है, लेकिन आधुनिकरण और शहरीकरण ने अब उनकी आजीविका को भी खतरे में डाल दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई बार तो उन्हें अपने मूल परिवारों का अंतिम संस्कार करने तक की जगह नहीं मिलती क्योंकि जिस गाँव

या इलाके से वह गुजर रहे होते हैं वहां के लोग उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे में उनके साथ हमारा साथ होना समाज मानवता का कितना परिचय देता होगा, समझा जा सकता है। हालाँकि यह दुखद आंकड़े ही हमें उनके बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित भी करते हैं।

सुझाव में घुमंतु समाज को सामाजिक और शैक्षिक रूप से आबोसी की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। यह कदम

उन्हें सरकारी योजनाओं, आरक्षण, और अन्य लाभों तक पहुंच प्रदान करेगा। यह न केवल उनकी गरिमा को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर भी देगा। दूसरा उपाय उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर के कॉमन आइडेंटिटी कार्ड से जोड़कर किया जा सकता है। यह कार्ड घुमंतू समाज के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगा। उनके लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए यह कार्ड उन्हें कहीं से भी मतदान करने, राशन लेने, बच्चों को स्कूल भेजने, अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने और रोजगार के अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाना सुनिश्चित कर सकता है। कम शब्दों में समझें तो यह कार्ड उनकी पहचान को एकजुट करेगा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करेगा, चाहे वे कहीं भी हों।

इसके अलावा, राज्यों में तहसील स्तर पर धर्मशाला जैसी अस्थायी आवास सुविधा का निर्माण भी किया जा सकता है। इन स्थानों पर स्वच्छता, पेयजल, बिजली और सुरक्षा जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। यह न केवल उनके जीवन को सम्मानजनक बनाएगा, बल्कि उनकी घमकड़ी प्रकृति को भी संरक्षित रखेगा।

हमें एक आदर्श समाज का उदाहरण बनते हुए यह नहीं भूलना चाहिए कि घुमंतू समाज भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत हिस्सा है। उनकी अनूठी जीवनशैली को सम्मान देते हुए, हमें उद्देश्यधारा में शामिल करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत ने सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। निश्चित तौर पर इन सुझावों को लागू कर के, घुमंतू समाज का जीवन स्तर बेहतर किया जा सकता है और भारत के समावेशी विकास के सपने को और मजबूती दी जा सकती है।

लाइन से आशीष जायसवाल, व्यायाम शिक्षक भूपेन्द्र वैष्णव, आत्मरक्षा प्रशिक्षक भानुप्रसाद साहू सिल्लिकी विद्यालय के शिक्षकगण और छात्र-छात्राएँ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। *इस तरह रजत जयंती वर्षों के अंतर्गत आयोजित यह कार्यक्रम बालिकाओं के आत्मविश्वास, जागरूकता और सर्वाधिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

